एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार एक **एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति (Integrated Clean Energy Policy) शुरू करने के लिये तैयार है, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में** कई नए प्रोत्साहन शामिल हैं, जिनमें **पंप भंडारण, हरित हाइड्रोजन, बैटरी भंडारण और जैव-ऊर्जा** जैसे उभरते क्षेत्र शामिल हैं।

- जयपुर में राज्य सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेशकों के साथ 6.57 लाख करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु

- **ऊर्जा पूर्व शिखर सम्मेलन** में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य **राजस्थान को एक ऊर्जा-अधिशेष राज्य बनाना है, जो अपनी ऊर्जा मांगों को पूर्ण करने में सक्षम हो** तथा दूसरों की सहायता कर सके।
- **नवीकरणीय ऊर्जा की ओर परिवर्तन:**
    - मुख्यमंत्री ने नई स्वच्छ ऊर्जा नीति के महत्व पर चर्चा की और राजस्थान में **नवीकरणीय ऊर्जा** के विकास की दिशा में ध्यान केंद्रित किया। इस नीति के अंतर्गत **2,245 मेगावाट क्षमता वाले विश्वस्तरीय सौर पार्क की स्थापना की जाएगी, जिससे 325 दिनों से अधिक** की वार्षिक धूप का उपयोग किया जा सकेगा।
    - नीति का उद्देश्य सौर, पवन और हाइब्रिड प्रौद्योगिकियों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में राजस्थान की क्षमता का लाभ उठाना है।
- **शिखर सम्मेलन पूर्व एवं निवेश प्रस्ताव:**
    - ऊर्जा प्री-शिखर सम्मेलन का आयोजन दिसंबर में होने वाले **राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024** से पहले किया गया।
    - **हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoU)** में सौर, पवन, हरित हाइड्रोजन, हाइब्रिड सिस्टम, पंप भंडारण, बैटरी भंडारण और **हरित अमोनिया** से संबंधित प्रस्तावित परियोजनाएँ शामिल हैं।
- **रोज़गार सृजन और आर्थिक प्रभाव:**
    - निवेश प्रस्तावों से जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के माध्यम से राजस्थान में लगभग 70,000 नए रोजगार सृजित होने की आशा है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/integrated-clean-energy-policy